



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1941 (श10)

(सं0 पटना 809) पटना, सोमवार, 15 जुलाई 2019

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

26 जून 2019

सं0 प्र0वि01-25/2018-2785—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा-10(1)(क), 10(1)(ख), 10(3), 16(1)(क), 16(1)(ख) और 16(2) को प्रभावी करने के लिए बनाए गए नियमों, यथा— बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधिक्रमण में बिहार के राज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं —

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:—**

- (1) यह नियमावली बिहार उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, बिहार और बिहार राज्य के जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषाएँ:—**

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:—

- (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68);
- (ख) 'जिला उपभोक्ता फोरम' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 9 के खंड (क) के अधीन स्थापित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम;
- (ग) 'सदस्य' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) (ख) के अधीन नियुक्त जिला उपभोक्ता फोरम का सदस्य अथवा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) (ख) के अधीन नियुक्त राज्य आयोग का सदस्य;
- (घ) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है यथास्थिति अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) (क) के अधीन नियुक्त जिला फोरम का अध्यक्ष अथवा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) (क) के अधीन नियुक्त राज्य आयोग का अध्यक्ष;
- (ङ) 'चयन समिति' से अभिप्रेत है, यथास्थिति धारा, 10 (1क) अथवा धारा 16 (1क) के अधीन गठित चयन समिति;

- (च) 'राज्य आयोग' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 9 के खंड (ख) के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग;
- (छ) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके प्रति क्रमशः समनुदेशित किए गए हों।

### 3. जिला उपभोक्ता फोरम में नियुक्ति की प्रक्रिया –

- (1) जिला उपभोक्ता फोरम का अध्यक्ष सेवारत जिला न्यायाधीशों से या तो सीधी नियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा।

परन्तुक, सेवारत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय, पटना की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

परन्तुक, यह और कि जहाँ वर्ष के प्रारम्भ में जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष पाँच सौ से अधिक शिकायतें लंबित हों अथवा पिछले तीन वर्षों में दायर औसतन शिकायतें पाँच सौ से अधिक न हों तो आधार पर अंशकालिक नियुक्ति की जा सकेगी।

- (2) उपनियम (1) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए, भी यदि राज्य सरकार का यह मत होता हो कि किसी सेवारत जिला न्यायाधीश को अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य किया जा सकता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ऐसा किया जा सकेगा।
- (3) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर नियुक्त किये जा सकेंगे :

परन्तुक, पूर्णकालिक नियुक्ति के लिए पदों की संख्या राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार के अध्यक्ष के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा चिह्नित की जायेगी।

परन्तुक, यह और कि जहाँ जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित शिकायतें पाँच सौ से अधिक न हो अथवा पिछले तीन वर्षों में दायर औसतन शिकायतें पाँच सौ से अधिक न हो तो नियुक्ति अंशकालिक आधार पर की जा सकेगी।

- (4) जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष वर्ष के प्रारम्भ में एक हजार पाँच सौ से अधिक लंबित शिकायतें अथवा पिछले तीन वर्षों में एक हजार से अधिक औसतन शिकायतें होने की दशा में राज्य सरकार जिला में एक अतिरिक्त जिला फोरम स्थापित कर सकेगी।
- (5) अंशकालिक आधार पर नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य सप्ताह में उतने दिन कार्य करेंगे जो राज्य आयोग के अध्यक्ष, जिला फोरम के कार्य भार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के परामर्श से विनिश्चित किया जायेगा।

परन्तुक, एक सप्ताह में कार्य दिवस की संख्या दो से कम नहीं होगी और अंशकालिक आधार पर नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्य दिवसों में नियमित कार्यालय समय का अनुपालन किया जायेगा।

- (6) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते समय अथवा कार्य करने का तात्पर्य रखते समय अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा-21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

### 4. राज्य आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया –

- (1) राज्य आयोग में अध्यक्ष पूर्णकालिक रूप से अथवा उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को अतिरिक्त प्रभार देकर नियुक्त किया जा सकेगा।

परन्तुक, उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की या तो पूर्णकालिक आधार पर या अतिरिक्त प्रभार देकर नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

- (2) राज्य आयोग के सदस्य या तो (क) सीधी नियुक्ति द्वारा या (ख) वैसे सरकारी सेवकों, जो पद धारण करने के लिए अर्हित हों, में से प्रतिनियुक्त पर नियुक्त किये जा सकेंगे।

परन्तुक, सेवारत न्यायाधिक पदाधिकारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

परन्तुक, यह और कि जहाँ राज्य आयोग के समक्ष वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें और अपील पाँच सौ से अधिक न हों अथवा पिछले तीन वर्षों में औसतन शिकायतें और दायर अपील पाँच सौ से अधिक न हों, तो नियुक्ति अंशकालिक आधार पर की जा सकेगी।

- (3) अंशकालिक आधार पर नियुक्त सदस्य सप्ताह में उतने दिन कार्य करेंगे जो राज्य आयोग का अध्यक्ष जिला फोरम के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के परामर्श से विनिश्चित किया जायेगा।

परन्तुक, एक सप्ताह में कार्य दिवस की संख्या दो से कम नहीं होगी और अंशकालिक आधार पर नियुक्त सदस्य अपने कार्य दिवसों में नियमित कार्यालय समय का अनुपालन किया जायेगा।

- (4) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते समय अथवा कार्य करने का तात्पर्य रखते समय अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा-21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।
- (5) **जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन –**
- (1) जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित विषय पर राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
  - (2) रिक्ति होने के कम से कम छह माह पूर्व नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।
  - (3) यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य के त्याग पत्र अथवा मृत्यु अथवा नये पद के सृजन के कारण कोई पद रिक्त होता है तो पद को भरने की प्रक्रिया, यथास्थिति, पद के खाली होने अथवा सृजित होने के ठीक पश्चात् आरंभ की जाएगी।
  - (4) पात्र अभ्यर्थियों से पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करनेवाला रिक्ति संबंधी विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी अन्य रीति से भी इसे परिचालित किया जाएगा जो राज्य आयोग का अध्यक्ष उचित समझे।
  - (5) जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन अधिनियम की धारा 10 की उपधारा-(1 क) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
  - (6) आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची उनके आवेदन पत्रों के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
  - (7) चयन समिति निम्नलिखित प्रक्रिया से आवेदकों का चयन करेगी, यथा:-
  - (क) न्यायिक पृष्ठभूमि रखनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पारित निर्णयों और अन्य न्यायिक आदेशों के आधार पर;
  - (ख) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम में कार्य करने का अनुभव रखनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में, पिछले दस वर्षों के उनके उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन और जिस पद के लिए आवेदन किया गया है उससे सुसंगत उनके अनुभव के आधार पर;
  - (ग) अन्य मामलों में, निम्नलिखित स्कीम के अनुसार दो पत्रों की लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर हरेक पत्र के लिए अर्हक अंक 50 प्रतिशत होगा:

पत्र	विषय	परीक्षा की प्रकृति	पूर्णांक	समय
पत्र I	(क) सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय (ख) भारत संविधान का ज्ञान (ग) अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपभोक्ता संबंधी विभिन्न विधियों का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटा
पत्र II	(क) व्यापार एवं वाणिज्य, उपभोक्ता संबंधी मामले अथवा सार्वजनिक मामले जैसे विषयों में से चयनित विषय पर निबंध (ख) विश्लेषण क्षमता की जाँच करने तथा तर्कपूर्ण आदेशों के प्रारूपण के लिए, एक उपभोक्ता मामले का केस अध्ययन,	वस्तुनिष्ठ	100	3 घंटा

- (8) चयन समिति चयनित सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी जिसमें व्यक्तित्व, सुसंगत पिछले अनुभव, विधि के ज्ञान, विशेष उपलब्धि, अभिरुचि और लिये गए समनुदेशन पर उनकी दृष्टि पर सम्यक अधिमान देते हुए अंक दिए जा सकेंगे।
- (9) चयन समिति राज्य सरकार के विचारार्थ योग्यता के क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों में से यथास्थिति अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नाम का एक पैनल अनुशंसित करेगी।
- (10) राज्य सरकार अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रत्यय पत्रों और पूर्ववृत्तों को सत्यापित करेगी अथवा करवाएगी।
- (11) अध्यक्ष अथवा सदस्य की हरेक नियुक्ति असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) अथवा जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परिशिष्ट में यथा उपदर्शित रूप में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सुपुर्द करने के अध्वधीन होगी।

- (12) नियुक्ति के पूर्व चयनित अभ्यर्थी को एक वचनबद्ध प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास कोई ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हित नहीं है तथा नहीं होगा जिससे अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना हो।

**6. राज्य आयोग के अध्यक्ष का चयन –**

- (1) नियुक्ति की प्रक्रिया रिक्ति होने के कम से कम छह माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा आरंभ की जाएगी।
- (2) यदि अध्यक्ष के त्याग पत्र अथवा नये पद के सृजन के कारण कोई पद रिक्त होता है तो पद को भरने की प्रक्रिया, यथास्थिति, पद के खाली होने अथवा सृजित होने के ठीक पश्चात् आरंभ की जाएगी।
- (3) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1क) के अधीन गठित चयन समिति योग्यता और अनुभव के आधार पर उपयुक्तता का निर्धारण करने के पश्चात् खोज और चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतीक्षा सूची के किसी अभ्यर्थी का किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ अनुशंसा राज्य सरकार के विचारार्थ करेगी।
- (4) विचारणीय अभ्यर्थी निगरानी की दृष्टि से मुक्त होगा।
- (5) राज्य सरकार चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात् करेगी।
- (6) अध्यक्ष की हरेक नियुक्ति असैनिक शल्य चिकित्सक अथवा जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परिशिष्ट में यथा उपदर्शित रूप में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सुपुर्द करने के अध्यक्षीन होगी।
- (7) नियुक्ति के पूर्व चयनित अभ्यर्थी को एक वचनबद्ध प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास कोई ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हित नहीं है तथा नहीं होगा जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना हो।

**7. राज्य आयोग के सदस्यों का चयन –**

- (1) नियुक्ति की प्रक्रिया रिक्ति होने के कम से कम छह माह पूर्व राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा आरंभ की जाएगी।
- (2) यदि सदस्य के त्याग पत्र अथवा मृत्यु अथवा नये पद के सृजन के कारण कोई पद रिक्त होता है तो पद को भरने की प्रक्रिया यथास्थिति पद के खाली होने अथवा सृजित होने के ठीक पश्चात् आरंभ की जाएगी।
- (3) पात्र अभ्यर्थियों से पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करनेवाला रिक्ति का विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी अन्य रीति से भी इसे परिचालित किया जाएगा जो राज्य आयोग के अध्यक्ष उचित समझे।
- (4) राज्य आयोग के सदस्यों का चयन अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1क) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
- (5) आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची उनके आवेदन पत्रों के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- (6) चयन समिति निम्नलिखित रीति से आवेदकों का चयन करेगी, यथा:—
  - (क) न्यायिक पृष्ठभूमि रखनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पारित निर्णयों और अन्य न्यायिक आदेशों के आधार पर,
  - (ख) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम में कार्य करने का अनुभव रखनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में, पिछले दस वर्षों के उनके उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन और जिस पद के लिए आवेदन किया गया है उससे सुसंगत उनके अनुभव के आधार पर,
  - (ग) अन्य मामलों में, निम्नलिखित स्कीम के अनुसार दो पत्रों की लिखित परीक्षा के आधार पर हरेक पत्र के लिए अर्हक अंक 50 प्रतिशत होगा।

पत्र	विषय	परीक्षा की प्रकृति	पूर्णांक	समय
पत्र I	(क) सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय (ख) सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तृत ज्ञान (ग) अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपभोक्ता संबंधी विभिन्न विधियों का ज्ञान (घ) भारत संविधान का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटा
पत्र II	(क) व्यापार एवं वाणिज्य, उपभोक्ता संबंधी मामले अथवा सार्वजनिक मामले जैसे विषयों में से चयनित विषय पर निबंध (ख) विश्लेषण क्षमता की जाँच करने तथा तर्कपूर्ण आदेशों के प्रारूपण के लिए, एक उपभोक्ता मामले का केस अध्ययन,	वस्तुनिष्ठ	100	3 घंटा

- (7) चयन समिति चयनित सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और व्यक्तित्व, सुसंगत पिछले अनुभव, निर्णयों की गुणवत्ता, विधि के ज्ञान, विशेष उपलब्धि, अभिरूचि एवं लिए गए समनुदेशन पर उनकी दृष्टि पर सम्यक् अधिमान देते हुए अंक देगी।
- (8) चयन समिति योग्यता के क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों में से सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नाम का एक पैनल राज्य सरकार के विचारार्थ अनुशंसित करेगी।
- (9) राज्य सरकार अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रत्यय पत्रों और पूर्ववृत्तों को सत्यापित करेगी अथवा करवाएगी।
- (10) सदस्य की हरेक नियुक्ति असैनिक शल्य चिकित्सक अथवा जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परिशिष्ट में यथा उपदर्शित रूप में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सुपुर्द करने के अध्यक्षीन होगी।
- (11) नियुक्ति के पूर्व चयनित अभ्यर्थी को एक वचनबद्ध प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास कोई ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हित नहीं हैं तथा नहीं होगा जिससे ऐसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना हो।

**8. जिला उपभोक्ता फोरम के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन/पारिश्रमिक –**

- (1) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त सेवारत जिला न्यायाधीश को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे, जो उन्हें पैतृक विभाग में धारित पद पर प्राप्त होता है।
- (2) सेवारत अथवा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश से भिन्न पूर्णकालिक अध्यक्ष जिला न्यायाधीश के वेतनमान के न्यूनतम वेतन एवं यथाग्राह्य अन्य भत्ते के समतुल्य समेकित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा।
- (3) पूर्णकालिक सदस्य को राज्य सरकार के उप सचिव के वेतनमान के न्यूनतम वेतन एवं यथाग्राह्य अन्य भत्ते के बराबर समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
- (4) अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर पूर्णकालिक रूप से नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का वेतन निर्धारण अंतिम आहरित वेतन में से पुनर्नियोजित पेंशन भोगी के पेंशन की राशि तथा यथाग्राह्य अन्य भत्ते के योग को घटाकर किया जाएगा।
- (5) पूर्णकालिक नियुक्त व्यक्ति के पारिश्रमिक का पुनरीक्षण 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के रूप में किया जाएगा।

**9. जिला उपभोक्ता फोरम के अंशकालिक अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन/पारिश्रमिक –**

- (1) अंशकालिक अध्यक्ष को बैठक के लिए प्रतिदिन X वर्ग के शहरों के लिए पाँच हजार रुपये, Y वर्ग के शहरों के लिए चार हजार तथा अन्य जगहों के लिए तीन हजार रुपये पाँच सौ रुपये का समेकित पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा।
- (2) अंशकालिक सदस्य को बैठक के लिए प्रतिदिन X वर्ग के शहरों के लिए चार हजार रुपये, Y वर्ग के शहरों के लिए तीन हजार पाँच सौ रुपये तथा अन्य जगहों के लिए दो हजार पाँच सौ रुपये का समेकित पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा।
- (3) अंशकालिक नियुक्त व्यक्ति के पारिश्रमिक की समीक्षा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए हरेक तीन वर्ष में की जाएगी।
- (4) अतिरिक्त प्रभार के आधार पर की गयी नियुक्ति की दशा में पारिश्रमिक वित्त नियमावली के सुसंगत उपबंधों द्वारा शासित होगी।

**10. राज्य आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन/पारिश्रमिक –**

- (1) राज्य आयोग के अध्यक्ष को वही वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियाँ प्राप्त होगी जो राज्य के उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को ग्राह्य हों।
- (2) राज्य आयोग के पूर्णकालिक सदस्य को राज्य सरकार के अपर सचिव के वेतनमान के न्यूनतम वेतन और यथाग्राह्य अन्य भत्ते के समतुल्य पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त सेवारत सरकारी सेवक प्रतिनियुक्ति वालों पर लागू उपबंधों के अधीन वेतन और भत्ते का हकदार होगा।

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति, जो पूर्णकालिक रूप से अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर नियुक्त हों, के वेतन का निर्धारण अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन की राशि को घटाकर किया जाएगा।

**11. राज्य आयोग के अंशकालिक सदस्यों के वेतन/पारिश्रमिक –**

- (1) राज्य आयोग के अंशकालिक सदस्य को बैठक के लिए प्रतिदिन X वर्ग के शहरों के लिए पाँच हजार रुपये, Y वर्ग के शहरों के लिए चार हजार रुपये तथा अन्य जगहों के लिए तीन हजार रुपये का समेकित पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा।
- (2) अंशकालिक नियुक्त व्यक्ति के पारिश्रमिक की समीक्षा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए हरेक तीन वर्ष में की जाएगी।
- (3) अतिरिक्त प्रभार के आधार पर की गयी नियुक्ति की दशा में पारिश्रमिक यथा संशोधित वित्त नियमावली के सुसंगत उपबंधों द्वारा शासित होगी।

**12. पूर्णकालिक नियुक्त व्यक्ति की छुट्टी और चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधा –**

पूर्णकालिक नियुक्त व्यक्ति राज्य सरकार के समूह 'क' पर लागू उपबंधों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा।

**13. वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भत्तों का भुगतान राज्य सरकार की संचित निधि से किया जायेगा।**

14. राज्य आयोग और जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन एवं शर्तें उनकी पदावधि के दौरान उनके प्रतिकूल परिवर्तित नहीं किए जायेंगे।

15. विशेष परिस्थितियों में राज्य आयोग और जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाना—

- (1) राज्य सरकार अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी जो:—
  - (क) दिवालिया घोषित हो चुका हो, अथवा
  - (ख) किसी अपराध में सिद्धदोष हो चुका है और जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल हो, अथवा
  - (ग) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हो चुका हो, अथवा
  - (घ) ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित कर चुका हो जिससे अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, अथवा
  - (ङ) अपने पद पर बने रहने के लिए अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जो लोकहित के प्रतिकूल हो, अथवा
  - (च) छुट्टी अथवा ऐसे कारण जो उसके नियंत्रण में न हो को छोड़कर लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।
- (2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश द्वारा जाँच किए बिना, जिसमें राज्य आयोग के अध्यक्ष को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सूचित किया गया हो तथा उन आरोपों के विरुद्ध सुने जाने का अवसर दिया गया हो तथा दोषी पाया गया हो, उस उप नियम के खंड (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट आधारों पर अपने पद से नहीं हटाया जाएगा।
- (3) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य आयोग के सदस्य, जिला फोरम के अध्यक्ष अथवा सदस्य राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित राष्ट्रीय आयोग के सदस्य द्वारा जाँच किए बिना, जिसमें यथास्थिति जिला फोरम के अध्यक्ष अथवा सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सूचित किया गया हो और उन आरोपों के विरुद्ध सुने जाने का अवसर दिया गया हो तथा दोषी पाया गया हो, उस उपनियम के खंड (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट आधारों पर अपने पद से नहीं हटाया जाएगा।

**16. व्यावृत्ति—** बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधिक्रमण के होते हुए भी, उक्त नियमावली के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कोई कार्रवाई एतद्वारा प्रभावित नहीं होगी।

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत कोई आदेश या परिपत्र जो इस संशोधन नियमावली के विरुद्ध हो उसे निरसित समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
पंकज कुमार,  
सरकार के सचिव।

*The 26<sup>th</sup> June 2019*

No. P2B1-25/2018/2785-Food—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), and in supersession of the rules made to give effect to sections 10(1)(a), 10(1)(b), 10(3), 16(1)(a), 16(1)(b) and 16(2), namely "The Bihar Consumer Protection Rules 1987 (as amended from time to time), the Governor of Bihar hereby makes the following Rules :—

**1. Short title, extent and commencement. —**

- (1) These rules may be called the Bihar Consumer Protection (appointment, salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission and District Forum) Rules, 2019.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Definitions. -** In these rules, unless otherwise required in the context —

- (a) 'Act' means the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986);
- (b) 'District Forum' means the District Consumer Disputes Redressal Forum established under clause (a) of section 9 of the Act;
- (c) 'Member' means a Member of the District Forum appointed under sub-section (1) (b) of Section 10 of the Act; or a Member of the State Commission appointed under sub-section (1) (b) of Section 16 of the Act, as the case may be;
- (d) 'President' means the President of the District Forum appointed under subsection (1) (a) of Section 10 of the Act; or the President of the State Commission appointed under sub-section (1) (a) of Section 16 of the Act, as the case may be;
- (e) 'Selection committee' means the Selection Committee constituted under section 10(1A) or section 16(1A), as the case may be;
- (f) 'State Commission' means the State Consumer Disputes Redressal Commission established under clause (b) of section 9 of the Act;
- (g) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

**3. Mode of appointments in District Fora.—**

- (1) President of a District Forum may be appointed either (a) by direct appointment or (b) on deputation from amongst the serving District Judges.

Provided that appointment of a serving District Judge may not be made without the concurrence of the High Court.

Provided further that where the pendency of complaints at the starting of the year before a District Forum does not exceed five hundred or the average number of complaints filed in the last three years does not exceed five hundred, the appointment may be made on part-time basis.

- (2) Notwithstanding the provisions in sub-rule (1), if the State Government is of the view that the work can be managed by assigning additional charge to a serving District Judge, it may be made so with the concurrence of the Chief Justice of the High Court.
- (3) Members of the District Forum may be appointed on whole-time basis or part time basis.

Provided that the number of posts for whole-time appointment shall be identified by the State Government, in consultation with the President of the State Commission :

Provided further that where the pendency of complaints at the starting of the year before a District Forum does not exceed five hundred or the average number of complaints filed in the last three years does not exceed five hundred, the appointment may be made on part-time basis.

- (4) In case of pendency of complaints at the starting of the year before a District Forum exceeding one thousand five hundred or the average number of complaints filed in the last three years exceeding one thousand, the State Government may establish an additional District Forum in the District.
- (5) Presidents and Members appointed on part-time basis shall function for such number of days in a week as may be decided by the President of the State Commission, in consultation with the State Government, taking into consideration the work load of the District Forum:

Provided that the number of working days shall not be less than two in a week and the President and Members, appointed on part-time basis, will observe regular office hours on their working days.

- (6) Presidents and Members while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

#### **4. Mode of appointment in the State Commission. –**

- (1) President of the State Commission may be appointed on whole time basis or by assigning additional charge to a sitting judge of the High Court:

Provided that appointment of a sitting High Court Judge, either on whole time basis or on additional charge basis, shall not be made without the concurrence of the Chief Justice of the High Court.

- (2) Members of the State Commission shall be appointed either by (a) direct appointment or (b) on deputation from amongst the Government servants, who are qualified to hold the post:

Provided that a serving judicial officer shall not be appointed without concurrence of the Chief Justice of the High Court.

Provided further that where the pendency of complaints and appeals at the starting of the year before the State Commission does not exceed five hundred or the average number of complaints and appeals filed in the last three years does not exceed five hundred, the appointment may be made on part-time basis.

- (3) Members appointed on part-time basis shall function for such number of days in a week as may be decided by the President of the State Commission, in consultation with the State Government, taking into consideration the work load of the District Forum:

Provided that the number of working days shall not be less than two in a week and the Members, appointed on part-time basis, will observe regular office hours on their working days.

- (4) Presidents and Members while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.



**5. Selection of the President and Members of District Forum. –**

- (1) Matters relating to appointment of President and Members of District Forum shall be processed by the President of the State Commission.
- (2) The process of appointments shall be initiated at least six months before the vacancy arises.
- (3) If a post falls vacant due to resignation or death of a President or a Member or creation of a new post, the process for filling the post shall be initiated immediately after the post has fallen vacant or is created, as the case may be.
- (4) The Advertisement of a vacancy, inviting applications for the posts from eligible candidates will be published in leading newspapers and also circulated in such other manner as the President of the State Commission may deem appropriate.
- (5) Selection of President and Members of District Forum shall be made by the Selection Committee constituted under sub-section (1A) of section 10 of the Act.
- (6) After scrutiny of the applications received till the last date specified for receipt of applications, list of eligible candidates along with their applications shall be placed before the Selection Committee.
- (7) The Selection Committee shall short-list the applicants in the following manner, namely—
  - (a) in case of candidates having judicial background, on the basis of the judgements and other judicial orders passed by such candidates;
  - (b) in case of candidates having experience of working under the Central Government or any State Government or an undertaking under the Central Government or the State Government, on the basis of their available Annual Confidential Reports for the last ten years and their experience relevant to the post applied for;
  - (c) in other cases, on the basis of performance in a written test consisting of two papers as per the following scheme. The qualifying marks in each paper shall be 50%:

Paper	Topics	Nature of test	Max. marks	Duration
Paper- I	(a) General Knowledge and current affairs (b) Knowledge of Constitution of India (c) Knowledge of various Consumer related Laws as indicated in the schedule.	Objective Type	100	2 hours
Paper- II	(a) One Essay on topics chosen from issues on trade & commerce, consumer related issues or Public Affairs (b) One case study of a consumer case for testing the abilities of analysis and cogent drafting of orders	Descriptive type	100	3 hours

- (8) The selection committee shall interview all shortlisted candidates in which marks may be awarded giving due weightage to the personality, relevant past experience, knowledge of law, special achievements, aptitude and vision for the assignment to be taken up.

- (9) The selection committee shall recommend a panel of names of candidates for appointment as President or Member, as the case may be, from amongst the candidates in the order of merit for consideration of the State Government.
- (10) The State Government shall verify or cause to be verified the credentials and antecedents of the recommended candidates.
- (11) Every appointment of a President or Member shall be subject to submission of a certificate of physical fitness as indicated in the annexure signed by a civil surgeon or District Medical Officer.
- (12) Before appointment, the selected applicant shall have to furnish an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as President or Member.

**6. Selection of the President of the State Commission. –**

- (1) The process of appointment shall be initiated by the State Government at least six months before the vacancy arises.
- (2) If a post falls vacant due to resignation or death of a President or creation of a new post, the process for filling the post shall be initiated immediately after the post has fallen vacant or is created, as the case may be.
- (3) The Selection Committee constituted under sub-section (1A) of section 16 of the Act, shall recommend, through a search and selection process after assessing the suitability on the basis of merit and experience, a candidate with another candidate in the waiting list, for consideration of the State Government.
- (4) The candidates under consideration shall be clear from the vigilance angle.
- (5) The State Government shall appoint the selected candidate after consultation with the Chief Justice of the High Court.
- (6) Every appointment of the President shall be subject to submission of a certificate of physical fitness as indicated in the annexure signed by a civil surgeon or District Medical Officer.
- (7) Before appointment, the selected candidate shall have to furnish an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as President.

**7. Selection of Members of the State Commission. –**

- (1) The process of appointments shall be initiated by the President of the State Commission at least six months before the vacancy arises.
- (2) If a post falls vacant due to resignation or death of a Member or creation of a new post, the process for filling the post shall be initiated immediately after the post has fallen vacant or is created, as the case may be.
- (3) The Advertisement of a vacancy, inviting applications for the posts from eligible candidates will be published in leading newspapers and also circulated in such other manner as the President of the State Commission may deem appropriate.
- (4) Selection of Members of the State Commission shall be made by the Selection Committee constituted under sub-section (1A) of section 16 of the Act

- (5) After scrutiny of the applications received till the last date specified for receipt of applications, a list of eligible candidates along with their applications shall be placed before the Selection Committee.
- (6) The Selection Committee shall short-list the applicants in the following manner, namely—
- in the case of candidates having judicial background, on the basis of the judgements and other judicial orders passed by such candidates;
  - in the case of candidates having experience of working under the Central Government or any State Government or an undertaking under the Central Government or the State Government, on the basis of their available Annual Confidential Reports for the last ten years and their experience relevant to the post applied for;
  - In other cases, on the basis of a written test of two papers as per the following scheme. The qualifying marks in each paper shall be 50%.

Paper- I	Topics	Nature of test	Max. marks	Duration
Paper- I	(a) General Knowledge and Current Affairs (b) Broad features of the Code of Civil Procedure (c) Knowledge of various Consumer related Laws as indicated in the schedule. (d) Knowledge of Constitution of India	Objective Type	100	2 hours
Paper- II	(a) One Essay on topics chosen from issues on trade & commerce, consumer related issues or Public Affairs (b) One case study of a consumer case for testing the abilities of analysis and cogent drafting of orders.	Descriptive type	100	3 hours

- (7) The Selection Committee shall interview all the shortlisted candidates and award marks with due weightage to the personality, relevant past experience, quality of the judgments, knowledge of law, special achievements, aptitude and vision for the assignment to be taken up.
- (8) The selection committee shall recommend a panel of names of candidates for appointment as Member from amongst the candidates in the order of merit for the consideration of the State Government.
- (9) The State Government shall, verify or cause to be verified the credentials and antecedents of the recommended candidates.
- (10) Every appointment of a Member shall be subject to submission of a certificate of physical fitness as indicated in the annexure signed by a civil surgeon or District Medical Officer.
- (11) Before appointment, the selected candidate shall have to furnish an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Member.

**8. Salaries/Remunerations of the whole-time President and Members of District Forum. –**

- (1) A serving District Judge, appointed on deputation basis, shall be entitled to such pay and allowances as was being paid for the post he held in the parent department.
- (2) A whole-time President other than serving or retired District Judge shall receive a consolidated remuneration equivalent to pay at the minimum of the scale of pay of a District Judge plus other allowances as admissible.
- (3) A whole-time Member shall be paid a consolidated remuneration equal to the pay at the minimum of the scale of pay of a Deputy Secretary of the State Government plus other allowances as admissible.
- (4) Fixation of pay of the retired Government servants appointed to the posts of President or Members on whole time basis shall be on the basis of the pay last drawn reduced by the amount of pension plus other allowances as admissible to a re-employed pensioner;
- (5) There shall be an annual upward revision of the remuneration of whole-time appointees at the rate of 3%.

**9. Salaries/Remunerations of the part-time President and Members of District Fora. –**

- (1) A part time President shall be paid a consolidated remuneration of rupees five thousand in class X cities, rupees four thousand in class Y cities and rupees three thousand in other places, per day of sitting.
- (2) A part time Member shall be paid a consolidated remuneration of rupees four thousand in X class cities, rupees three thousand and five hundred in Y class cities and rupees two thousand and five hundred in other places, per day of sitting.
- (3) Remuneration of the part-time appointees shall be reviewed every three years taking into consideration the consumer price index.
- (4) Remuneration in the case of appointments made on additional charge basis shall be governed by the relevant provisions in the Financial Rules.

**10. Salaries/Remunerations of the whole-time President and Members of the State Commission. –**

- (1) President of the State Commission shall receive the same salary, allowances and other perquisites as are admissible to a sitting judge of the High Court of the State.
- (2) A whole-time Member of the State Commission shall be paid a remuneration equivalent to the pay at minimum of the scale of pay of an Additional Secretary in the State Government and other allowances as admissible:

Provided that serving Government servants appointed on deputation basis shall be entitled to salary and allowances under the provisions applicable to deputationists.

Fixation of pay of the persons retired from Government service, appointed to the posts of President or Member on whole time basis, shall be on the basis of the pay last drawn reduced by the amount of pension.

**11. Salaries/Remuneration of the part-time Members of the State Commission. –**

- (1) A part-time Member of the State Commission shall be paid a consolidated remuneration of rupees five thousand in X class cities, rupees four thousand in Y class cities and rupees three thousand in other places, per day of sitting.
- (2) Remuneration of the part-time appointees shall be reviewed every three years taking into consideration the consumer price index.
- (3) Remuneration in the case of appointments made on additional charge basis shall be governed by the relevant provisions in the Financial Rules as amended.

**12. Leave and Medical treatment and hospital facilities to the whole-time appointees:—**

Whole-time appointees shall be entitled to leave, LTC, medical treatment and hospital facilities as per the provisions applicable to Group A Government servants in the State Government.

**13.** The salary, remuneration and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government and in case of the Union Territories, from the Consolidated Fund of India.

**14.** The terms and conditions of the service of the President and the Members of the District Forum and the State Commission shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

**15. Removal of President and Members of State Commission and District Forum from office in certain circumstances. –**

- (1) The State Government may remove from office, the President or any Member, who, —
  - (a) has been adjudged as an insolvent; or
  - (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
  - (c) has become physically or mentally incapable of acting as the President or the Member; or
  - (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the President or a Member; or
  - (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or
  - (f) remains absent in three consecutive sittings except without leave or for reasons beyond his control.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), the President of the State Commission shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d), (e) and (f) of that sub-rule except after an inquiry held by a sitting Judge of the High

Court nominated by the Chief Justice of the High Court in which the President of the State Commission has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges and found guilty.

- (3) Not with standing anything contained in sub rule (1) a Member of the State commission, President or Member of the District Forum shall not be

removed from his office on the grounds specified in clauses (d), (e) and (f) of that sub-rule except after an inquiry held by a Member of the National Commission nominated by the President of the National Commission, in which the President or Member of the District Forum or the Member of the State Commission, as the case may be, has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges and found guilty.

16. Savings- Notwithstanding the supersession, the Bihar Consumer Protection Rules, 1987 (as amended from time to time), anything done or any action taken under the said Rules shall not be hereby affected.

Any circular or order issued by the State Government earlier repugnant to these amended Rules shall be deemed repealed.

By order of Governor of Bihar,  
PANKAJ KUMAR,  
*Secretary.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 809-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>